नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 016
दि. 16.05.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

यूपी में आयुष्मान योजना में धांधली रोकने के लिए योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 100 अस्पताल निलंबित; सौ का भुगतान रोका

(जीएनएस)।

लखनऊ। योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेह बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले निजी चिकित्सालयों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि योजना के लाभार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अस्पतालों की सूचीबद्धता और गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया को किया गया और अधिक सख्त

साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में इसे अधिक प्रभावी, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए समय-समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

इसी दिशा में अस्पतालों की सूचीबद्धता और गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाया गया है। योगी सरकार द्वारा अस्पताल इम्पैनलमेंट मॉड्यूल (एचईएम) पोर्टल के माध्यम से सूचीबद्ध अस्पतालों का सत्यापन निर्धारित मानकों के आधार पर किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत अस्पतालों के लिए 35 महत्वपूर्ण मानकों को पूरा करना अनिवार्य किया गया है। इनमें अस्पताल का पंजीकरण प्रमाणपत्र, फायर सेफ्टी एनओसी, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सकों की शैक्षणिक योग्यता, एचएफआर पंजीकरण सहित अन्य जरूरी दस्तावेज और व्यवस्थाएं शामिल हैं।

सीईओ ने बताया कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट हेल्थ एजेंसी की ओर से ई-मेल, दूरभाष, संदेश, पत्राचार और वर्चुअल बैठकों के माध्यम से अस्पतालों को हर स्तर पर सहायता दी गई। इसका सकारात्मक परिणाम यह रहा कि अब तक 95 प्रतिशत से अधिक अस्पताल सफलतापूर्वक एचईएम 2.0 पोर्टल पर माइग्रेट हो चुके हैं। हालांकि, कुछ निजी अस्पतालों ने निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं की। योगी सरकार की ओर से उन्हें कई बार अवसर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद करीब 200 निजी चिकित्सालयों ने मानकों के अनुरूप प्रक्रिया पूरी नहीं की।

इनमें आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अमेठी, अमरोहा, आजमगढ़, बागपत, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फरुर्खाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, प्रतापगढ़, संतकबीरनगर, सुल्तानपुर, वाराणसी, शाहजहांपुर, जालौन, मिर्जापुर, अंबेडकरनगर, रामपुर और सोनभद्र सहित कई जिलों के अस्पताल शामिल हैं।

सीएम योगी के निर्देश पर ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 100 अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया है, जबकि करीब 100 अन्य अस्पतालों को योजना से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को केवल मानक आधारित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं ही प्राप्त हों।

बता दें कि योगी सरकार ने सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को एनएबीएच गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही राज्य और जिला स्तर पर अस्पतालों की नियमित ऑडिट और मॉनिटरिंग भी कराई जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को समय रहते रोका जा सके। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक के अधिकतम उपयोग पर भी विशेष जोर दे रही है। अस्पतालों में डिजिटल माध्यम से मरीजों के निस्तारण को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एबीडीएम सक्षम एचएमआईएस प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (ईएचआर) प्रणाली को भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इससे मरीजों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा और इलाज की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और तेज होगी। राज्य स्तर से अस्पतालों को पोर्टल संचालन और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही ऐसे मामलों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिनमें चिकित्सकों की डिग्री अथवा विवरण के अनुचित उपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

पिछड़े वर्ग को त्वरित न्याय दिलाने में जुटी योगी सरकार, 87% से ज्यादा शिकायतों का किया निस्तारण

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के संकल्प के साथ सभी वर्गों को न्याय दिला रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग लगातार शिकायतों की सुनवाई कर त्वरित निस्तारण कर रहा है. आयोग साल 2024 से अप्रैल 2026 तक आई कुल शिकायतों में से करीब 87 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निस्तारण कर चुका है. इस तरह आयोग ने योगी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए न केवल बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निस्तारण किया है, बल्कि नई शिकायतों पर भी समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की है.

87 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का हुआ निस्तारण

दरअसल योगी सरकार की प्राथमिकताओं में पिछड़ा वर्ग के लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान, शिकायतों की सुनवाई और प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई शामिल है. इसी क्रम में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सक्रियता से बड़ी संख्या में लोगों को न्याय मिला है.

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2024 से अप्रैल 2026 तक कुल 3394 शिकायतें आई थीं. इनमें से 2962 मामलों की सुनवाई और कार्यवाही के बाद निस्तारण किया जा चुका है. इस तरह करीब 87 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है.

छात्र-छात्राएं भी छात्रवृत्ति और शैक्षणिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर आयोग से मदद मांगते हैं. साथ ही पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए भी लोग आयोग में प्रत्यावेदन देते हैं. उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों की अनुसूची-एक में जातियों के सम्मिलन, निष्कासन और संशोधन से संबंधित कुल 324 प्रत्यावेदन प्राप्त हुए.

इनमें से 307 मामलों का सुनवाई और कार्यवाही के बाद निस्तारण किया जा चुका है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य केवल शिकायतें प्राप्त करना नहीं, बल्कि पीड़ित लोगों को वास्तविक राहत पहुंचाना है.

गृह मंत्री को धमकी देने के आरोप में ममता बनर्जी के अभिषेक बनर्जी भतीजे पर एफआईआर, कौन-कौन सी लगी धाराएं?

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे घोषित होने के महज एक दिन बाद तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव और डायमंड हार्बर लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज इस एफआईआर को राज्य पुलिस द्वारा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पहली बड़ी कानूनी कार्रवाई माना जा रहा है।

सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की लिखित शिकायत पर बागुइयाटी पुलिस स्टेशन में प्रारंभिक शिकायत दर्ज हुई, जिसे बाद में साइबर क्राइम यूनिट को ट्रांसफर कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने अभिषेक बनर्जी पर चुनाव प्रचार के दौरान कई जगहों पर दिए गए भड़काऊ भाषणों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का आरोप लगाया है।

एफआईआर में कौन-कौन सी धाराएं?

पुलिस ने कुल 5 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है:

BNS 192 (जमानती): दंगे भड़काने से संबंधित।

BNS 196 (गैर-जमानती): विभिन्न समूहों के बीच सद्भाव बिगाड़ना और घृणा फैलाना।

BNS 351(2) (गैर-जमानती): मृत्यु की धमकी देना और मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाना।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) और 125: चुनाव

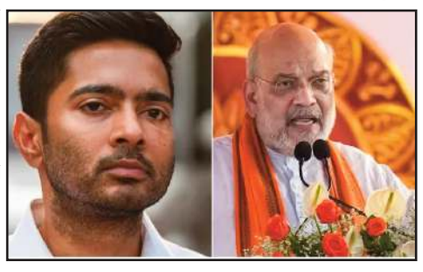

प्रचार के दौरान भ्रामक बयान, दबाव और समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना।

ये धाराएं गंभीर हैं और अभिषेक बनर्जी की संसदीय सदस्यता तथा राजनीतिक भविष्य पर भी असर डाल सकती हैं।

विवाद की जड़: चुनावी रैलियों में दिए गए भाषण

2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। परिणाम आने से पहले और बाद में अभिषेक बनर्जी ने कई रैलियों में इखढ, अमित शाह, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए थे।

शिकायतकर्ता राजीव सरकार ने अभिषेक के विभिन्न भाषणों के वीडियो लिंक और क्लिप्स संलग्न कर शिकायत दी। आरोप है कि इन भाषणों में:

अमित शाह को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाकर धमकी भरे बयान दिए गए।

प्रधानमंत्री मोदी की अपील की गुजरात में बड़ा असर, दो दिनों में पायलट वाहनों की मांग घटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और सरकारी यात्राएं कम करने की अपील का गुजरात में बड़ा असर देखने को मिला है। पिछले दो दिनों में पायलट वाहनों की मांग में कमी दर्ज की गई है। शुक्रवार को राज्य सरकार ने पिछले दो दिनों में गृह विभाग को पायलट वाहन के लिए आने वाली कॉल्स में कमी की जानकारी दी।

गांधीनगर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और सरकारी यात्राएं कम करने की अपील का गुजरात में बड़ा असर देखने को मिला है। पिछले दो दिनों में पायलट वाहनों की मांग में कमी दर्ज की गई है। शुक्रवार को राज्य सरकार ने पिछले दो दिनों में गृह विभाग को पायलट वाहन के लिए आने वाली कॉल्स में कमी की जानकारी दी।

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक से पहले कहा कि पायलट वाहनों की संख्या घटाने से ईंधन के इस्तेमाल और मैनपावर में काफी बचत हुई है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाने के प्रयास भी तेज किए हैं।

नए उपायों के असर पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए संघवी ने

कहा, "कुल मिलाकर दो दिनों में 126 कॉल्स की कमी आई है।"

उन्होंने कहा कि अगर कम से कम अनुमान भी लगाया जाए, तो इस कमी से लगभग 5,000 किलोमीटर तक पेट्रोल और डीजल की खपत में बचत हो सकती है। उन्होंने कहा, "अगर हम हर कॉल के लिए औसतन 25 से 50 किलोमीटर की दूरी मान लें, तो कम से कम 5,000 किलोमीटर के बराबर डीजल और पेट्रोल की बचत होगी।"

उन्होंने आगे बताया कि इस बचत पर एक औपचारिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हर्ष संघवी ने यह भी बताया कि हर पायलट वाहन की तैनाती में कुछ कर्मचारी शामिल होते हैं, जिन्हें अब दूसरे कामों में लगाया जा सकता है।

राज्य सरकार ने ये कदम प्रधानमंत्री मोदी की हालिया सार्वजनिक अपील के बाद उठाए हैं, जिसमें उन्होंने नागरिकों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने, कारपूलिंग अपनाने और जहां संभव हो, अधिकतर बैठकें ऑनलाइन करने का आग्रह किया था।

इस अपील के बाद से गुजरात के प्रशासनिक कामकाज में कई बदलाव किए गए हैं। मंत्रियों ने अपने काफिले को छोटा किया है, जबकि विभागों को सलाह दी गई है कि जहां भी व्यावहारिक हो, वे वर्चुअल बैठकें करें।

संघवी ने कहा कि गांधीनगर तक की अनावश्यक यात्रा कम करने पर खास फोकस है।

पीएम मोदी इस साल करेंगे रूस दौरा : लावरोव

नई दिल्ली। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस साल के अंत में रूस जाएंगे। लावरोव के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान खुद इस बात की पुष्टि की।

गुरुवार को लावरोव ने नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी। लावरोव ने भारत में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद कहा कि मास्को कई क्षेत्रों में भारत के साथ अपनी 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लावरोव ने कहा, "हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की कि इस वर्ष रूस का दौरा करने की उनकी बारी है। भारत-रूस साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है।"

दोनों देश द्विपक्षीय लेनदेन में अमेरिकी डालर पर निर्भरता कम करते हुए राष्ट्रीय मुद्राओं में लेनदेन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लावरोव ने स्पष्ट किया कि रूस उन सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है।

हैदराबाद-जयपुर स्पेशल एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, AC के दो डब्बे जलकर हुए खाक

हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब जयपुर जाने वाली हैदराबाद-जयपुर स्पेशल एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। ट्रेन के डिब्बों से उठती तेज लपटों और धुएं ने पूरे स्टेशन पर हड़कंप मचा दिया, लेकिन समय रहते की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया।

शुक्रवार शाम लगभग सात बजे रवाना होने वाली इस ट्रेन के थ्री-टियर एसी कोच के इ1 और इ2 डिब्बों में अचानक आग लग गई। कुछ ही पलों में धुआं और आग की लपटें फैलने लगीं।

खट्टर ने 50वीं वर्षगांठ पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बीबीएमबी सहयोगी देशों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करता है

बीबीएमबी ने राज्यों को दी गई सेवाओं के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया

(जीएनएस)।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में एक कार्यक्रम के दौरान भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा जल और बिजली संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन पर प्रकाश डाला। 15 मई, 1976 को अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाते हुए, खट्टर ने बिजली, सिंचाई, सामाजिक-आर्थिक विकास, कृषि उन्नति और क्षेत्रीय विकास में बीबीएमबी के योगदान की प्रशंसा की।

बीबीएमबी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सेवा प्रदान करते हुए, भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर बांधों से जल वितरण की देखरेख करता है। खट्टर ने बढ़ती बिजली की मांगों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों, पंप स्टोरेज प्लांट्स (पीएसई) और बैटरी-स्टोरेज समाधानों के

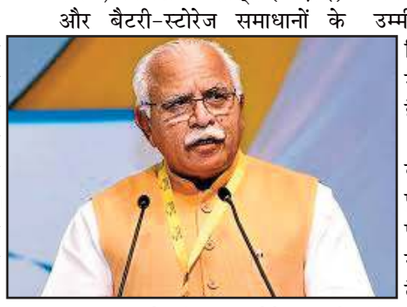

महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि बीबीएमबी पदों के लिए पंजाब और हरियाणा के उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

खट्टर ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों की प्रमुख बीबीएमबी पदों पर नियुक्ति की परंपरा को अब औपचारिक रूप दिया गया है। उन्होंने कहा, "हम इन पदों पर चयन के लिए पंजाब और हरियाणा के उम्मीदवारों को वरीयता देंगे।" इस निर्णय का उद्देश्य बोर्ड के नेतृत्व में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बनाए रखना है।

पंजाब के जल संसाधन मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने पंजाब पुलिस के बजाय बीबीएमबी परियोजनाओं में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने नियुक्ति नियमों में बदलाव को अनावश्यक बताते हुए आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र ने हाल ही में अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को अनुमति देने के लिए बीबीएमबी पदों के लिए पात्रता मानदंडों को संशोधित किया था।

होशियारपुर में बोरवेल में गिरने के बाद चार वर्षीय गुरकरण सिंह को बचाया गया

पंजाब के होशियारपुर जिले में एक बोरवेल में गिर जाने के बाद चार साल के गुरकरन सिंह को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। यह घटना शुक्रवार रात को भिकारवाल के पास चक समाना गांव में हुई। सिंह 20 से 30 फीट की गहराई में फंसे हुए थे, जिसके कारण कई एजेंसियों और स्थानीय स्वयंसेवकों को मिलाकर नौ घंटे का बचाव अभियान चलाया गया।

गुरकरण सिंह को बोरवेल से बचाया गया, बचाव दलों ने सिंह को लगभग 12:40 बजे बाहर निकाला और चिकित्सा मूल्यांकन के लिए अस्पताल ले गए। मिट्टी से ढके होने के बावजूद, वे स्थिर दिखे। एनडीआरएफ के उप कमांडेंट पंकज शर्मा ने बच्चे की स्थिति स्थिर होने की पुष्टि की, और अभियान के दौरान ढीली मिट्टी से उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख किया।

भगवंत मान सरकार की शिक्षा क्रांति का असर, पंजाब के 416 सरकारी स्कूलों की 12वीं कक्षा का रिजल्ट 100 प्रतिशत रहा

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार की शिक्षा क्रांति के तहत पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 416 सरकारी स्कूलों ने 100 प्रतिशत पास प्रतिशत दर्ज कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

हाल ही में आए 12वीं के नतीजों में लड़कियों ने एक बार फिर मेरिट सूची और पास प्रतिशतता में बाजी

मारी है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 500 में 500 अंक हासिल कर अव्वल रहने वाली पंजाब की तीन बेटियों मानसा की सुपनीत कौर, लुधियाना की सुहानी चौहान और दिवांशी की भरपूर प्रशंसा करते हुए कहा कि लड़कियां शिक्षा के पुनरुत्थान का नेतृत्व कर रही हैं।

सरकारी स्कूलों में शिक्षा के प्रति विश्वास को और मजबूत करते हुए, मेरिट सूची में शामिल 275 विद्यार्थियों में से 122 विद्यार्थी सरकारी स्कूलों के हैं। यह आप सरकार के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण, आधुनिक क्लासरूमों और केंद्रित शैक्षणिक सुधारों से लैस पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मानसा की सुपनीत कौर, लुधियाना की सुहानी चौहान और दिवांशी को 500 में 500 अंक प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इन विद्यार्थिनियों को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए 50,000 रुपए की नकद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया।

'मोदी जी, योगी जी आप अपनी सुरक्षा कम मत करिए', रवि किशन ने दुश्मन देशों का जताया डर! कहा- मैं साइकिल से चलूंगा

(जीएनएस)।

गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात की है।

गोरखपुरः उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सुरक्षा कम किए जाने के मसले पर एक खास अपील की है। इसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल, सीएम योगी शुक्रवार को गोरखपुर के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे थे। सांसद रवि किशन भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो गाड़ी पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ऐसा कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमत के कारण लोगों को संदेश देने के लिए इस प्रकार इन नेताओं ने सुरक्षा में कमी की है, लेकिन यह खतरनाक है।

गोरखपुर सांसद रवि किशन ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा आवश्यक है। हम लोगों ने काफिला लेकर चलना बंद कर दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से चल रहे हैं। आप कहेंगे तो हम ईवी छोड़कर साइकिल से चल लेंगे, लेकिन

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपना काफिला काम नहीं करना चाहिए। उनकी सुरक्षा अधिक जरूरी है।

रवि किशन ने इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि पूरी दुनिया आप पर नजर रखती है। इसमें कई आतंकवादी संगठन और हमारे दुश्मन पड़ोसी देश भी शामिल हैं। आप कृपया अपनी सुरक्षा कम नहीं करें। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे अधिक जरूरी है। रवि किशन के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद यूजर्स ने भी उनके समर्थन में बातें कहीं।

गोरखपुर में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिम एशिया युद्ध का संकट झेल रहा है। ईंधन की आपूर्ति बाधित हो गई है। दुनिया के लगभग सभी देशों में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं। अमेरिका ने तो पेट्रोलियम पदार्थों के दाम चार गुना तक बढ़ा दिए हैं। यूरोपीय देशों की हालत खराब है। पाकिस्तान किसी प्रकार समय काट रहा है। अरब देश अंधकार में रहने के लिए मजबूर हैं। अमेरिका ईरान युद्ध का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि 12 फरवरी से लगातार युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है।

सीएम योगी ने कहा कि जनता पर अधिक बोझ न आए, इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था की है। पीएम मोदी ने इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए लोगों से विदेश न घूमने जाने और सोना न खरीदने की अपील की है। प्रधानमंत्री की मंशा भारत का पैसा भारत में रहने की है। इसलिए हमें अपने प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करना चाहिए।

गोरखपुर में भी अब होंगे आईपीएल के मैच, सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कर्मभूमि गोरखपुर को हर खेल सुविधा से समृद्ध करना चाहते हैं। रामगढ़ ताल वाटर स्पोर्ट्स के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है। अब बारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार 16 मई को गोरखपुर की उपलब्धियों की श्रृंखला में स्वर्णाक्षरों जड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेल अवस्थापना सुविधाओं के लिहाज से गोरखपुर का नाम वैश्विक स्तर पर उल्लिखित कराने तथा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए शनिवार को क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। करीब 393 करोड़ रुपये की लागत वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे।

गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में है। इस संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रशासन की तरफ से ताल नदोर

में उपलब्ध कराई गई जमीन पर 24 दिसंबर 2025 से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

औपचारिक शिलान्यास होने से पहले सरकार की तरफ से जारी परियोजना लागत की प्रथम किश्त 63.39 करोड़ रुपये से काम आगे बढ़ रहा है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड एक (भवन) के अनुसार अब तक करीब सात प्रतिशत काम हुआ है। स्टेडियम का निर्माण 23 दिसंबर 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा।

गोरखपुर में बन रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 46 एकड़ क्षेत्रफल में आकार लेगा। 30 हजार दर्शक क्षमता का यह स्टेडियम 'ग्राउंड प्लस टू फ्लोर' के हिसाब से बनेगा। मेन ग्राउंड पर खिलाड़ियों के लिए सात प्लेइंग पिच और चार प्रैक्टिस पिच होगी। यहां स्टेडियम के पूर्वी और पश्चिमी स्टैंड में प्रत्येक में 14,490 दर्शक बैठ सकेंगे। नार्थ पैवेलियन 208 वीआईपी व 382 मीडियाकर्मियों और साउथ पैवेलियन 1708 वीवीआईपी व वीआईपी के लिए होगा। रात्रिकालीन मैच भी हो सकें, इसके लिए मेन स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मानक के चार हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था रहेगी। यहां क्रिकेट के अलावा अन्य बड़े आयोजन भी होंगे।

ताल नदोर में बन रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहतरीन जगह पर है। गोरखपुर-वाराणसी राजमार्ग फोरलेन से जुड़ा यह स्थान, गोरखपुर एयरपोर्ट से करीब 24 किमी की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से करीब 20 किमी है। ऐसे में खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए यहां पहुंचना काफी सुगम होगा।

गोरखपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में देश की शीर्ष पेट्रोलियम कंपनियां अपने सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) फंड से कुल 100 करोड़ रुपये देंगी। एमओयू के बाद धनराशि आवंटन प्रक्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम निर्माण के लिए सीएसआर फंड से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड साठ करोड़ रुपये, भारत पेट्रोलियम तीस करोड़ और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दस करोड़ रुपये देगी।

एसएस मोता सिंह स्कूल मामले में सियासी विवाद गहराया, ट्रस्ट और फाइल गायब होने पर आम आदमी पार्टी का आरोप

(जीएनएस)।

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जिस एसएस मोता सिंह स्कूल में तीन साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसका राजनीतिक संबंध होने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री आशीष सूद की गलत बयानी पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार में एसएस मोता सिंह स्कूल की फाइल गायब हो गई है।

आशीष सूद बताएं कि सरकार क्या छिपाना चाहती है? ट्रस्ट में आने-जाने वाले सदस्यों की सारी जानकारी सरकार के सब रजिस्ट्रार को दी जाती है। वह फाइल कैसे गायब हो गई? उन्होंने पूछा कि अगर स्कूल का कोई राजनीति संबंध नहीं है तो फिर अमरजीत सिंह बब्बू ने फेसबुक पर ट्रस्टी बनाने का सारा श्रेय मंत्री प्रवेश वर्मा को देते हुए उन्हें धन्यवाद क्यों किया?

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्कूल के ट्रस्ट में अमरजीत सिंह के अलावा डॉ. वीरेंद्र कुमार अग्रवाल, स्वाति गर्ग और मनीष गुप्ता नए ट्रस्टी बने हैं। फेसबुक पर पोस्ट करने से अमरजीत सिंह बब्बू के बारे कुछ जानकारी मिल गई, लेकिन बाकी तीन लोग कौन हैं?

बच्ची के पैरेंट्स का कहना है कि वे जब भी थाने गए, तो स्कूल के जनकपुरी ब्रांच के मैनेजर मनजीत सिंह ओलख वहां मिले, जो मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के करीबी हैं और साथ में दोनों की फोटो भी है। उन्होंने कहा कि आज तीन साल की रेप पीड़ित बच्ची तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्पताल में भर्ती है। इसके बावजूद स्कूल मैनेजमेंट को क्यों बचाया जा रहा है? उन्होंने आशीष सूद से स्कूल की फाइल सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि स्कूल का राजनीतिक संबंध है या नहीं है।

शुक्रवार को "आप" मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एसएस मोटा सिंह पब्लिक स्कूल में जिस तीन साल की बच्ची से स्कूल के ही एक अधिकारी ने उसके

साथ रेप किया। उस बच्ची को परिजन जब दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले गई, तो रात में करीब सवा दो बजे उसका मेडिकल हुआ। मेडिकल करने वाली डॉक्टर ने लड़की की मां से कहा था कि बच्ची का हाइमन रप्चर हो गया है, लेकिन बाद में डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट के अंदर इस बात को नहीं लिखा।

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि उसके बाद से लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने खाना-पीना बेहद कम कर दिया था और उसे यूरिन पास करने तक में तकलीफ हो रही थी। परिवार ने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें भी बच्ची को काफी दिक्कतें बताई गईं।

गुरुवार को उस बच्ची की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। मां-बाप के हालात ऐसे हैं कि वे फोन करके पूछ रहे हैं कि अगर पैसे की दिक्कत हुई और सरकार ने पैसे नहीं दिए तो वे क्या करेंगे? हमने परिवार से कहा है कि वे पैसे की चिंता न करें, उन्हें दिक्कत नहीं होने दी जाएगी और वे बस इलाज कराएं। मगर यह बड़े शर्म की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आज स्कूल जाने वाली एक मासूम बच्ची के साथ ऐसे हालात हो गए हैं।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अभी बच्ची की हालत कैसी है यह नहीं पता, लेकिन रात को उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया और वह अभी भी एडमिट है। बच्ची को सीवियर इंफेक्शन बताया गया है और यह इंफेक्शन क्यों होता है, यह सब लोग भली-भांति जानते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि अदालत ने आरोपी को कुछ दिन पहले ही बेल दे दी है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गुरुवार को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद पहली बार इस मामले पर बोले, जबकि यह उनके अपने क्षेत्र जनकपुरी का एक जाना-माना स्कूल है। यह स्कूल उनके घर से दो मिनट की दूरी पर है, इसलिए वे ऐसा नहीं कह सकते कि वे इस स्कूल को नहीं जानते।

मार्च में आशीष सूद ने खुद इस स्कूल के अंदर दिल्ली सरकार द्वारा भजन क्लबिंग वाला एक भव्य कार्यक्रम कराया था। हजारों लोग उसमें आए थे और लाखों या हो सकता है करोड़ों रुपए उस पर खर्च हुए हों। सरकार खर्चा तो बताती नहीं है और विधानसभा में भी नहीं बताती। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आशीष सूद दोनों मौजूद थे। ऐसे किसी अनजान स्कूल के अंदर सरकारें सरकारी खर्च से बड़े-बड़े प्रोग्राम नहीं रखा करतीं।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गुरुवार को आशीष सूद ने बहुत भद्दी और घटिया बात कही। वे कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज बताएं कि भाजपा के किस नेता और मंत्री ने इस स्कूल में स्टेक्स खरीदे हैं। जब शिक्षा मंत्री भाजपा के हैं, राजस्व मंत्री भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री भाजपा की हैं और सब रजिस्ट्रार दफ्तर भी उनका ही है, तो कागज सौरभ भारद्वाज कहां से लाएंगे? कागज तो भाजपा सरकार के पास ही हैं।

सौरभ भारद्वाज ने ट्रस्ट के खेल के बारे में बताते हुए कहा कि पांच-सात आदमियों का एक ट्रस्ट होता है जो स्कूल को चलाता है। एसएस मोता सिंह स्कूल के ट्रस्ट का नाम एसएस मोता सिंह नीला चैरिटेबल ट्रस्ट है। नीला पाकिस्तान के उस गांव का नाम है जहां से इसकी शुरूआत हुई थी।

इस ट्रस्ट के पास करीब 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। पश्चिम विहार में 7 एकड़, जनकपुरी में करीब ढाई एकड़ और 500 गज जमीन अलग से है। स्कूलों के ट्रस्ट का खेल यह होता है कि दो ट्रस्टी रिजाइन करते हैं और दो नए आ जाते हैं। फिर दो और रिजाइन करते हैं और दो नए आ जाते हैं। धीरे-धीरे पुराने ट्रस्टी गायब हो जाते हैं और नए ट्रस्टी आ जाते हैं, जिनमें से एक आदमी चेयरमैन बन जाता है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस तरह 500 करोड़ की संपत्ति कुछ हाथों से दूसरे हाथों में पहुंच जाती है और इसके लिए पैसे का सारा लेनदेन ब्लैक और कैश में होता है।

ऐसे ही कोई फ्री में ट्रस्ट देकर खुद हरिद्वार जाने की बात नहीं कह सकता। इस तरह के ट्रस्टों में जो लेनदेन होता है, वह ब्लैक में होता है। जबकि आदर्श रूप में यह लेनदेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें नॉन प्रॉफिट कहा जाता है।

जनगणना 2027: जम्मू के उपायुक्त ने 17 मई से शुरू होने वाली डिजिटल स्व-गणना में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित किया

(जीएनएस)।

जम्मू के उपायुक्त राकेश मिन्हास ने निवासियों से 17 मई से शुरू होने वाली जनगणना 2027 के लिए डिजिटल स्व-गणना प्रक्रिया में भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने गणनकों के आने पर सत्यापन के लिए परिवारों द्वारा अपनी स्व-गणना आईडी तैयार रखने के महत्व पर जोर दिया, जिससे परिचालन दक्षता बढ़ेगी और क्षेत्र सत्यापन का समय कम होगा।

डिजिटल स्व-गणना सुविधा 17 मई से 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। मिन्हास, जो जम्मू जिले के लिए प्रधान जनगणना अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं, ने घोषणा की कि आधिकारिक पोर्टल 17 मई को सुबह 6 बजे लाइव हो जाएगा। नागरिक एक सक्रिय मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार और व्यक्तिगत विवरण भर सकते हैं, फॉर्म जमा कर सकते हैं, और एक अद्वितीय स्व-गणना आईडी (SE ID) प्राप्त कर सकते हैं।

किसी भी वयस्क परिवार का सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार मोबाइल फोन, टैबलेट या कंप्यूटर का उपयोग करके प्रक्रिया पूरी कर सकता है। 1 जून से 30 जून तक, प्रशिक्षित गणनक घर-घर जाकर मकानों की सूची बनाने का कार्य करेंगे। इन कार्यों में 33 प्रश्नों वाले एक संरचित प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्र करना शामिल होगा, जो घरेलू सुविधाओं, स्वामित्व की स्थिति और अन्य सुविधाओं से संबंधित होंगे।

मिन्हास ने स्पष्ट किया कि स्व-गणना एक अतिरिक्त सुविधा है। जो निवासी डिजिटल प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ हैं, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 जून से 30 जून तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच सरकारी गणनक जिले के सभी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने उन परिवारों से आग्रह किया जिन्होंने स्व-गणना पूरी कर ली है, वे इन दौरों के दौरान सत्यापन के लिए अपनी रए कऊ तैयार रखें।

सभी गणनकों के पास सरकार द्वारा जारी वैध पहचान पत्र होंगे। मिन्हास ने निवासियों को जानकारी साझा करने से पहले उनकी पहचान सत्यापित करने की सलाह दी। उन्होंने जनगणना कार्यों के बहाने पैसे वसूलने की कोशिश करने वाले धोखेबाजों के खिलाफ भी चेतावनी दी, और दोहराया कि यह पूरी कवायद निःशुल्क है।

दिल्ली-एनसीआर में इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

(जीएनएस)।

दिल्ली-एनसीआर की हवा में घुलता जहर अब सिर्फ एक मौसमीय समस्या नहीं, बल्कि एक बड़ी नीति-क्रांति का कारण बन रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (उअदट) ने प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए ऐसे कड़े फैसले लिए हैं। जो आने वाले समय में न सिर्फ वाहनों की दुनिया बदल देंगे, बल्कि खेतों से उठने वाले धुएं तक पर सीधी चोट करेंगे। हालांकि दमघोंटू हवा से बचने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू होंगे, जिनका सीधा असर आमजन पर पड़ेगा।

दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल पंपों पर अब सख्त नियम लागू होंगे। 1 अक्टूबर 2026 से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (ठउफ) में 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' व्यवस्था अनिवार्य होगी। वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (ढवउ) के बिना कोई भी पेट्रोल पंप संचालक ईंधन नहीं देगा। आयोग ने यह कदम लोगों की पीयूसी बनवाने में लापरवाही सुधारने और हर वाहन के लिए प्रमाण पत्र सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।

प्रदूषण घटाने के लिए कामर्शियल

वाहन बाजार को भी बदला गया है। माल ढुलाई या सवारी ढोने वाले थ्री-व्हीलर (छ5 कैटेगरी) अब पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगे। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में किसी भी नए पेट्रोल, डीजल या सीएनजी ऑटो रिक्शा का पंजीकरण नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही पंजीकृत किए जाएंगे।

यह बदलाव दिल्ली तक सीमित नहीं। 1 जनवरी 2028 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), गाजियाबाद, सोनीपत जैसे अहम औद्योगिक शहरों में भी यही नियम लागू होगा। अंततः, 1 जनवरी 2029 से पूरे बचे एनसीआर में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही पंजीकृत होंगे, जो प्रदूषण रोकने में सहायक होगा।

सर्दियों में पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के खेतों से उठने वाला पराली का धुआं दिल्ली की हवा बिगाड़ देता है। इसके स्थायी समाधान हेतु उअदट ने 15 मई 2026 को 'डायरेक्शन नंबर 99' जारी किया। इसके तहत, तीनों राज्यों को एक कड़ा एक्शन प्लान मिला है, जिसमें 'पराली प्रोटेक्शन फोर्स' का गठन सबसे अहम कदम है।

इस एक्शन प्लान में हर खेत की डिजिटल मैपिंग व जवाबदेह नोडल अधिकारियों की तैनाती भी शामिल है। उअदट का लक्ष्य है कि 2026 के धान कटाई सीजन में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य पर लाया जा सके, जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रित होगा।

पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड सीबीआई ने धर दबोचा

(जीएनएस)।

पेपर लीक मामले में सीबीआई को शुक्रवार को बड़ी कामयाबी मिली है। सीबीआई ने इस केस के कथित मास्टरमाइंड बताए जा रहे पी.वी. कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, पीवी कुलकर्णी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसे प्रश्नपत्रों तक सीधी पहुंच मिलने की बात सामने आई है।

कुलकर्णी NEET UG परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े होने का फायदा उठाकर पेपर लीक नेटवर्क का हिस्सा बना और छात्रों तक सवाल-पहले ही पहुंचाने में भूमिका निभाई। आइए जानते हैं कौन हैं ये पीवी कुलकर्णी और कैसे पहुंचा इसके पास पेपर?

ठएएळ-वक्र 2026 ढंस्री१ छीं' हँङ्ग-२ ढश ङ४"१ल्ल? कौन हैं पी.वी. कुलकर्णी?

पी.वी. कुलकर्णी पुणे में केमिस्ट्री के लेक्चरर रहे हैं और रिटायर्ड प्रोफेसर बताए जा रहे हैं। वे मूल रूप से महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले हैं। सीबीआई के अनुसार, कुलकर्णी का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षा व्यवस्था से जुड़ाव था, जिसकी वजह से उन्हें प्रश्नपत्रों तक पहुंच मिलने की आशंका जताई जा रही है।

कैसे खुला पूरा मामला?

जांच एजेंसी के मुताबिक यह पूरा नेटवर्क तब सामने आया जब आरोपी मनीषा वाघमारे से पूछताछ की गई।

इसके बाद सीबीआई कुलकर्णी तक पहुंची और लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

"स्पेशल कोचिंग" चलाकर किया ये खेल

CBI के मुताबिक पीवी कुलकर्णी ने अप्रैल 2026 के आखिरी सप्ताह में एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे जिसे 14 मई 2026 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उसकी मदद से छात्रों को जुटाया था और पुणे स्थित अपने घर पर विशेष कक्षाएं चलाईं। यहां छात्रों को प्रश्न, उनके विकल्प और सही जवाब लिखवाए गए, जो बाद में 3 मई 2026 की ठ ए ए ळ - व ॠ परीक्षा के असली पेपर से हूबहू मेल खाते पाए गए।

सीबीआई ने देशभर के कई शहरों में बड़ी कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस दौरान जांच टीमों ने अहम दस्तावेज, मोबाइल फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। एजेंसी के मुताबिक, इन सभी सामग्रियों की फोरेंसिक और तकनीकी जांच तेजी से की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा सकें।

यह मामला 12 मई 2026 को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के बाद दर्ज किया गया था, जिसके तुरंत बाद देशभर में विशेष जांच टीमें सक्रिय कर दी गई थीं।

इससे पहले इस केस में जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

इनमें से पांच आरोपियों को अदालत में पेश कर सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं, गुरुवार को पकड़े गए दो अन्य आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली लाने के उद्देश्य से पुणे की अदालत में ट्रांजिट रिमांड पर पेश किया जा रहा है।

सीबीआई ने जांच में यह भी दावा किया है कि उन्हें केमिस्ट्री पेपर लीक का असली स्रोत और इसमें शामिल बिचौलियों का पता चल गया है।

बताया जा रहा है कि इन लोगों ने मोटी रकम लेकर छात्रों को विशेष कोचिंग कक्षाओं तक पहुंचाया। एजेंसी ने कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष, व्यापक और पेशेवर तरीके से जांच जारी रहेगी ताकि सभी दोषियों की पहचान की जा सके।

ग्रेटर नोएडा के फर्नीचर मार्केट में कैसे लगी आग? क्या थी वजह? कितना नुकसान?

(जीएनएस)।

ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में शुक्रवार (15 मई) शाम को भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि लपटें कई मीटर ऊंची उठ रही थीं और आसमान में घना काला धुआं छा गया। आसपास का इलाका धुंध में छिप गया। आग ने 4-5 फर्नीचर दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें लाखों रुपये का फर्नीचर, लकड़ी और अन्य सामान जलकर राख हो गया।

पुलिस और प्रशासन ने तुरंत आग पर काबू पाने के लिए कम से कम 8 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजीं। देर शाम तक आग बुझाने और शीतलन का काम जारी रहा। स्थानीय लोगों ने मोबाइल पर जो वीडियो बनाए, उनमें आग की भयावह तस्वीर साफ नजर आ रही है। लपटें छत फोड़कर बाहर निकल रही हैं और चारों तरफ धुएं का गुबार।

शाम के समय जब बाजार में सामान्य चहल-पहल थी, तभी अचानक एक दुकान से आग की लपटें उठनी शुरू हुईं। हवा के कारण आग तेजी से फैली और पास की कई दुकानों तक पहुंच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या विद्युत तंत्र की खराबी बताया जा रहा है, हालांकि आधिकारिक जांच अभी जारी है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां रवाना की गईं। आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि फर्नीचर मार्केट में लकड़ी, फोम, कपड़े और अन्य

ज्वलनशील सामग्री भरी हुई थी, जो आग को और भड़काती रही। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। दुकानदारों और मजदूरों ने समय रहते खुद को बाहर निकाल लिया।

नुकसान का अनुमान? 4-5 दुकानों को भारी नुकसान। लाखों रुपये का फर्नीचर, रेडीमेड सामान और कच्चा माल जलकर खाक। कई दुकानदारों की सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। आग की वजह से आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा।

NCR में आग की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? पुरानी इमारतें और विद्युत तंत्रः कई बाजारों और फैक्टरियों में पुरानी वायरिंग है, जो ओवरलोडिंग से शॉर्ट सर्किट का कारण बनती है। ज्वलनशील सामग्रीः फर्नीचर मार्केट में लकड़ी, पेंट, फोम और कपड़ा, ये सब आग को तेजी से फैलाते हैं। गर्मी का मौसमः मई में तापमान 40 डिग्री के पार होने से बिजली की मांग बढ़ती है और शॉर्ट सर्किट की आशंका बढ़ जाती है। सुरक्षा मानकों की अनदेखीः कई दुकानों और फैक्टरियों में फायर सेफ्टी उपकरण (अग्निशमन यंत्र, स्प्रिंकलर, निकास मार्ग) या तो नहीं हैं या काम नहीं कर रहे।

फायर सेफ्टी पर सवाल, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली-एनसीआर में बार-बार आग की घटनाएं फायर सेफ्टी सिस्टम की कमियों को उजागर करती हैं। क्या बाजारों में नियमित फायर ऑडिट होते हैं? क्या सभी दुकानों में फायर NOC लिया गया है? क्या मजदूरों और दुकानदारों को फायर ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाती है?

ये सवाल प्रशासन और नगर निगम पर उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों और दुकानदारों की प्रतिक्रिया- घटना स्थल पर मौजूद दुकानदारों ने बताया कि आग देखकर उनका खून सूख गया। एक दुकानदार ने कहा, 'सब कुछ जल गया। साल भर का सामान, लाखों का नुकसान। अब क्या करें?' स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग की तेजी की तारीफ की, लेकिन कहा कि आग लगने से पहले रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रशासन की प्रतिक्रिया, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया। प्रभावित दुकानदारों को मुआवजे और मदद का आश्वासन दिया गया है। पुलिस ने आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है। यदि लापरवाही पाई गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

गहराता संकट

जलडमरूमध्य पश्चिम एशिया में इस वक्त तनाव का मुख्य केन्द्र बना हुआ है जहां बुधवार को सुबह भारत के ध्वज वाली मशीनी पाल नौका हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में हमले का शिकार हो गई।

पोत पर सवार सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक दल ने सुरक्षित बचा लिया है। भारत सरकार ओमान प्रशासन और भारतीय राजदूतावास के साथ मिलकर सभी को भारत लाने का प्रयास कर रही है। दरअसल ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने जब हमला करके उनके नेताओं, शीर्ष सैन्य अधिकारियों तथा वैज्ञानिकों का सफाया कर दिया तो तेहरान ने जवाबी कार्रवाई में खाड़ी के देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तो हमला किया ही साथ ही उन देशों की सम्पत्तियों को भी निशाना बनाया जो अमेरिका द्वारा संरक्षित घोषित की गई हैं। युद्ध के दौरान पूरी दुनिया को अपने रणनीतिक महत्व का एहसास दिलाने के लिए होर्मूज जलडमरूमध्य को बाधित कर दिया।

वुछ मित्र देशों को छोड़कर ईरान ने सभी देशों की जहाजों को इस क्षेत्र से गुजरने की छूट नहीं दी।

अमेरिका ने जलडमरूमध्य से निर्बाध जहाजों को गुजरने के लिए ईरान को धमकाया भी किन्तु वहां की सेना और सिविल प्रशासन ने एक न सुनी। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने भी जलडमरूमध्य की घेराबंदी कर दी। आज भी ईरान और अमेरिका दोनों के सैनिक इस क्षेत्र में तैनात हैं।

सच तो यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध विराम हुआ है वह कभी भी दोबारा टूट सकता है। इस बार यदि युद्ध भड़का तो वह इतना विकराल होगा कि ईरान तो बर्बाद होगा ही खाड़ी के देश भी तबाह हो जाएंगे।

सच तो यही है कि एलपीजी गैस की महंगाई के वजह से 42 महीनों में भारत की मुद्रास्फीति 8 प्रतिशत पार कर गई है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था रूपी शरीर का मधुमेह होता है। इससे देश, संस्थानों और निजी आर्थिक स्थिति पर प्रतिवूल प्रभाव पड़ता है। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की संभावित कीमतों का अनुमान लगाकर ही देशवासियों से ईंधन कम खर्च करने का आग्रह करके इस बात की चेतावनी दी है कि यदि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध दोबारा छिड़ा तो भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिवूल असर पड़े बिना नहीं रहेगा।

इसलिए देश की जनता पहले से ही पेट्रोल, डीजल और वुकिग गैस को ज्यादा खर्च न करें अन्यथा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी कम से कम खर्च करने के अनुरोध के तुरन्त बाद खुद ही अपने काफिले में शामिल होने वाली 14 गाड़ियों को कम करके मात्र तीन गाड़ी में सीमित कर दिया। मतलब यह कि एक गाड़ी में खुद प्रधानमंत्री, एक गाड़ी अतिरिक्त और एक में सुरक्षाकमी होंगे। इसी तरह केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने अपने काफिले में शामिल गाड़ियों में 80 प्रतिशत तक की कटौती कर दी है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रियों ने काफिले को छोटा करके प्रधानमंत्री मोदी के पैसले का समर्थन किया है।

बहरहाल एक जहाज के हमले की चपेट में आने अथवा घात लगाकर हमला किए जाने से जलकर वह डूब गया। यह भारत के लिए अत्यन्त दुःख और चिन्ता बढ़ाने वाली बात है। इसलिए अब देश के सभी वगरे को ऊर्जा संरक्षण के प्रति सजग हो जाना चाहिए। जन सामान्य को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि निजी वाहन को वुछ दिन के लिए पेट्रोल व डीजल की जरूरत न पड़े। इसी तरह सीएनजी और एलपीजी गैस के खर्च को भी कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

दिल्ली दरबार पर भारी पड़ा जमीनी नेता, केरल में सतीशन क्यों बने कांग्रेस का चेहरा

(जीएनएस)।

वीडी सतीशन की जीत ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब केवल हाईकमान आधारित राजनीति के भरोसे नहीं चलना चाहती।

केरल में पाटा ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि जनता और कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता रखने वाला नेता ही सबसे बड़ा राजनीतिक निवेश होता है। यही कारण है कि इस बार दिल्ली की ताकत पर जमीन की हकीकत भारी पड़ गई।

दिल्ली दरबार पर भारी पड़ा जमीनी नेता, केरल में सतीशन क्यों बने कांग्रेस का चेहरा केरल की राजनीति में इस बार सिर्प सरकार नहीं बदली, कांग्रेस की अंदरूनी ताकत का नक्शा भी बदल गया। दस वर्षो बाद सत्ता में लौटी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक प्रंट सरकार ने जब वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री चुना तो यह पैसला केवल एक व्यक्ति को वुसा सौंपने का नहीं था, बल्कि कांग्रेस के भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाला कदम बन गया। चुनाव नतीजे आने के बाद लगभग दस दिनों तक दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक जिस तरह की खींचतान चली, उसने साफ कर दिया था कि यह लड़ाई सिर्प मुख्यमंत्री पद की नहीं, बल्कि कांग्रेस में दिल्ली मॉडल बनाम जमीनी मॉडल की थी।

आखिरकार पाटा ने संगठन महासचिव और राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने वाले केसी वेणुगोपाल के बजाय उस नेता पर भरोसा जताया, जिसने पांच वर्षो तक विपक्ष में रहकर कांग्रेस को दोबारा खड़ा किया।

2026 के विधानसभा चुनाव में 140 सदस्यीय विधानसभा में यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। कांग्रेस ने अकेले 63 सीटें हासिल कीं, जबकि उसकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतीं। एलडीएफ गठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। 2021 में कांग्रेस नीत यूडीएफ को सिर्प 41 सीटें मिली थीं और एलडीएफ 99 सीटों के साथ सत्ता में लौटा था।

यानी पांच वर्षो में कांग्रेस ने 22 सीटों की सीधी बढ़त दर्ज की, जबकि वाम मोर्चा 64 सीटें खो बैठा। यही आंकड़े बताते हैं कि यह जीत किसी सामान्य सत्ता विरोधी लहर का परिणाम नहीं थी, बल्कि विपक्ष के नेता के रूप में वीडी सतीशन की बनाई राजनीतिक रणनीति का असर थी।

दरअसल, 2021 की हार कांग्रेस के लिए केवल चुनावी पराजय नहीं थी, बल्कि संगठनात्मक संकट भी थी। पाटा के भीतर वर्षो से चल रही ए ग्रुप और आई ग्रुप की राजनीति ने कार्यकर्ताओं को थका दिया था।

ओमन चांडी और के. करुणाकरण के दौर से चली आ रही गुटबाजी ने कांग्रेस को जनता से दूर कर दिया था। ऐसे समय में राहुल गांधी ने रमेश चेन्निथला की जगह वीडी सतीशन को विपक्ष का नेता बनाया। उस समय यह पैसला जोखिम भरा माना गया, क्योंकि सतीशन के पास न दिल्ली की लॉबी थी और न ही संगठन पर वैसी पकड़, जैसी केसी वेणुगोपाल के पास मानी जाती थी। लेकिन पांच साल बाद वही पैसला कांग्रेस के पुनजावन की सबसे बड़ी वजह बन गया। सतीशन ने विपक्ष का नेता बनने के बाद सबसे पहले कांग्रेस की चुनावी राजनीति की शैली बदली। उन्होंने साफ कहा कि टिकट वितरण में गुटीय वफादारी नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता देखी जाएगी। इसका असर स्थानीय निकाय चुनावों में दिखाई दिया।

दिसंबर 2025 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ ने 941 पंचायतों में से 505 पर जीत हासिल की। 87 नगर पालिकाओं में से 54 यूडीएफ के खाते में गईं।

14 जिला पंचायतों में से 7 पर कब्जा हुआ, जबकि 6 में से 4 नगर

निगमों में कांग्रेस गठबंधन को सफलता मिली। इन नतीजों ने पहली बार यह संकेत दिया कि एलडीएफ की पकड़ कमजोर हो रही है और कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है।

सतीशन की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनकी डेटा आधारित राजनीति रही।

विधानसभा में उन्होंने सिर्प राजनीतिक आरोप नहीं लगाए, बल्कि सरकारी आंकड़ों के जरिए पिनाराई विजयन सरकार को घेरा।

केरल में बेरोजगारी दर, राज्य का बढ़ता कर्ज, सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार और युवाओं के पलायन जैसे मुद्दों को उन्होंने लगातार उठाया। सेंटर फॉर मॉनिटरिग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, 2025 में केरल की शहरी बेरोजगारी दर 18ट्ठ के करीब पहुंच गई थी, जबकि युवाओं में यह आंकड़ा 30ट्ठ से अधिक था।

पिछले पांच वर्षो में लगभग 18 लाख युवा रोजगार और शिक्षा के लिए राज्य से बाहर गए। सतीशन ने इन आंकड़ों को लगातार राजनीतिक मुद्दा बनाया और कांग्रेस को भविष्य की अर्थव्यवस्था की भाषा बोलने वाली पाटा के रूप में पेश किया। केरल की सामाजिक संरचना को समझे बिना इस पैसले को समझना मुश्किल है। राज्य की राजनीति में नायर, ईसाई और मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल दोनों नायर समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी राज्य में लगभग 14 से 15 प्रतिशत मानी जाती है।

लेकिन फर्व यह रहा कि सतीशन लगातार नायर बहुल परवूर सीट से पांच बार चुनाव जीत चुके हैं।

2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में उन्होंने लगातार जीत दर्ज की। इससे उनकी जमीनी पकड़ मजबूत मानी जाती है। दूसरी ओर, वेणुगोपाल लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में सव्रिय रहे और राज्य की सव्रिय राजनीति से उनकी दूरी बढ़ती गई।

कांग्रेस के लिए सबसे अहम बात यह थी कि सतीशन को अल्पसंख्यक समुदायों का भी व्यापक समर्थन हासिल था। केरल की लगभग 26ट्ठ आबादी मुस्लिम और करीब 18ट्ठ ईसाई है।

यूडीएफ की सबसे बड़ी सहयोगी आईयूएमएल शुरू से सतीशन के पक्ष में थी।

मुस्लिम लीग को यह आशंका थी कि अगर दिल्ली से कोई नेता मुख्यमंत्री बनकर आता है तो गठबंधन के भीतर संतुलन बिगड़ सकता है। चर्च समूहों के बीच भी सतीशन की छवि एक ऐसे नेता की रही, जो वैचारिक रूप से उदार हैं लेकिन धरमिक तुष्टिकरण की खुली राजनीति नहीं करते। यही वजह रही कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें सर्वस्वीकार्य चेहरा माना। केसी वेणुगोपाल की दावेदारी के सामने सबसे बड़ा संकट उनकी राजनीतिक स्थिति थी। वे लोकसभा सांसद हैं और पाटा महासचिव भी। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता तो पहले संसद सदस्यता छोड़नी पड़ती।

इसके बाद किसी विधायक की सीट खाली कराकर उन्हें छह महीने के भीतर विधानसभा पहुंचाना पड़ता। यानी एक लोकसभा और एक विधानसभा उपचुनाव का अतिरित्त जोखिम पैदा होता। कांग्रेस पहले ही जानती थी कि सत्ता में आने के बाद शुरूआती महीनों में किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता का संदेश नुकसानदेह साबित हो सकता है। यही कारण है कि अंतिम समय में हाईकमान ने कम जोखिम वाले विकल्प पर भरोसा जताया। इस पैसले का राष्ट्रीय राजनीतिक संदेश भी बड़ा है।

कांग्रेस लंबे समय से इस आलोचना का सामना करती रही है कि पाटा में पैसले सिर्प दिल्ली दरबार के आधार पर होते हैं।

लेकिन केरल में पाटा ने पहली बार साफ संकेत दिया कि अब चुनाव जिताने वाले क्षेत्रीय नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सतीशन की ताजपोशी कांग्रेस के भीतर पीढ़ीगत बदलाव का भी प्रतीक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल प्रमुख चेहरों केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला और वीडी सतीशन में सतीशन को अपेक्षावृत युवा और नई पीढ़ी के नेता के तौर पर देखा गया। उनका पूरा राजनीतिक अभियान नई कांग्रेस की अवधारणा पर आधारित था। भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकना भी इस पैसले के पीछे एक बड़ा कारण रहा।

सतीशन इस राजनीतिक संतुलन में फिट बैठते हैं। उनकी छवि आव्रामक सांप्रदायिक राजनीति से दूर लेकिन सांस्वृतिक रूप से जुड़ी हुई मानी जाती है।

अब सबसे बड़ी चुनौती वादों को जमीन पर उतारने की होगी। केरल इस समय लगभग 4 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। राज्य में निजी निवेश की रफ्तार धीमी है और युवाओं का पलायन लगातार बढ़ रहा है। सतीशन ने चुनाव के दौरान ग्लोबल जॉब नेटवर्व, शिक्षा सुधार और स्टार्टअप अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का वादा किया था। अगर वे इन मोर्चो पर ठोस परिणाम देते हैं तो कांग्रेस सिर्प केरल में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नया राजनीतिक मॉडल पेश कर सकती है। वीडी सतीशन की जीत ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब केवल हाईकमान आधारित राजनीति के भरोसे नहीं चलना चाहती। केरल में पाटा ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि जनता और कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता रखने वाला नेता ही सबसे बड़ा राजनीतिक निवेश होता है। यही कारण है कि इस बार दिल्ली की ताकत पर जमीन की हकीकत भारी पड़ गई।

केरलम में 26 मई को दस्तक देगा मानसून! आईएमडी ने बताई तारीख, आपके शहर में कब होगी बारिश?

(जीएनएस)।

भारत में भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी (क्टऊ) ने मानसून 2026 को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस साल दक्षिण-

पश्चिम मानसून के 26 मई 2026 को केरल पहुंचने की संभावना है, हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि डेट आगे-पीछे हो सकती है,अनुमान है कि ये 22 मई से 30 मई के बीच कभी भी केरल में दस्तक दे सकता है।

आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून हर साल 1 जून को केरल पहुंचता है। ऐसे में यदि मानसून 26 मई को आता है तो इसे सामान्य से पहले माना जाएगा। इससे किसानों, कृषि क्षेत्र और जल संकट से जूझ रहे राज्यों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस खबर के सामने आने के बाद बाराबंकी के किसान राम चरण दास ने कहा कि 'ये वाकई अच्छी खबर है।'

क्टऊ के अनुसार, मानसून के आगमन का पूवार्नुमान एक सांख्यिकीय मॉडल के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें समुद्र की सतह के तापमान, वायुमंडलीय दबाव, हवा की दिशा और हिंद महासागर की जलवायु स्थितियों जैसे कई कारकों का अध्ययन किया जाता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रारंभिक अनुमान है और आगे मौसम की परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव संभव है।

मानसून का जल्दी आना सुखद है: मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिशए, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश (लखनऊ) का मानना है कि 'अगर मानसून समय से पहले आता है और इसकी प्रगति सामान्य रहती है, तो देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से जल्दी राहत मिल सकती है, साथ ही खरीफ फसलों की बुवाई भी समय पर शुरू हो सकेगी। धान, कपास, सोयाबीन और मक्का जैसी फसलों के लिए समय पर बारिश बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।'

मानसून के पैटर्न में बदलाव देखा जा रहा है, मोहम्मद दानिश के मुताबिक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रही मौसमी परिस्थितियां मानसून को अनुकूल बना रही हैं। पिछले कुछ वर्षो में जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून के पैटर्न में बदलाव देखा गया है। कभी अत्यधिक बारिश तो कभी लंबे सूखे जैसी स्थितियां सामने आई हैं। ऐसे में इस बार मानसून के समय से पहले आने की खबर काफी अहम है।

केरल में पहले आता है मानसून, केरल में मानसून की दस्तक को भारत में बारिश के मौसम की औपचारिक शुरूआत माना जाता है। इसके बाद मानसून धीरे-धीरे कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर राज्यों, महाराष्ट्र और फिर उत्तर भारत की ओर बढ़ता है। सामान्य परिस्थितियों में जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून पूरे देश को कवर कर लेता है।

मानसून क्या है? मानसून एक मौसमी पवन प्रणाली है, जो साल के एक निश्चित समय पर अपनी दिशा बदलती है और भारी बारिश लेकर आती है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण दक्षिण-पश्चिम मानसून माना जाता है, जो जून से सितंबर तक देश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा करता है। यह मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आता है, जिससे पूरे देश में बारिश होती है।

कृषि प्रधान देश के लिए मानसून बेहद अहमए भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मानसून बेहद अहम है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है। अगर मानसून सामान्य रहे तो फसल अच्छी होती है, जलाशय भरते हैं और बिजली उत्पादन से लेकर पीने के पानी तक की जरूरतें पूरी होती हैं। भारत की लगभग 50-60 प्रतिशत खेती आज भी बारिश पर निर्भर मानी जाती है। ऐसे में मानसून देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जैसा है। मानसून कमजोर होने पर सूखे जैसी स्थिति हो जाती है, इसके कारण खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है, नदियां, तालाब और बांध भरते हैं, भूजल स्तर बढ़ता है, गर्मी से राहत मिलती है, बिजली उत्पादन में मदद मिलती है और पेड़-पौधों और पर्यावरण को जीवन मिलता है। अगर मानसून कमजोर पड़ जाए तो सूखा, पानी की कमी और महंगाई जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं अत्यधिक बारिश बाढ़ और नुकसान का कारण बनती है।

मैदान से दूर रहने के बावजूद गूंज रहा है माही का नाम

आईपीएल 2026 का सीजन अपने रोमांचक मोड़ पर है। लेकिन मैदान पर फैंस को थाला यानी महेंद्र सिंह धोनी की कमी खल रही है। कॉफ इंजरी के कारण धोनी इस सीजन में अब तक एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। भले ही धोनी डगआउट में बैठकर अपनी टीम का मार्गदर्शन कर रहे हों, लेकिन उनके संन्यास के सालों बाद भी वनडे क्रिकेट का एक ऐसा रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है, जिसके करीब पहुंचना भी आज के बल्लेबाजों के लिए एवरेस्ट चढ़ने जैसा है।

धोनी के नाम दर्ज है अनोखा रिकॉर्ड

वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में एमएस धोनी दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो 84 बार नॉट आउट पवेलियन लौटे हैं। एक फिनिशर के तौर पर धोनी ने मैच को अपने तरीके से खत्म करने में महारथ हासिल की। क्रिकेट के जानकार मानते हैं कि धोनी का यह रिकॉर्ड किसी भी खिलाड़ी के लिए तोड़ना

आसान नहीं होगा।

अंतिम ओवर में कई बार टीम को दिलाई जीत

धोनी के इस रिकॉर्ड की खासियत यह नहीं है कि वे अंत तक टिके रहे, बल्कि यह है कि वे दबाव वाले मौकों पर टीम को जीत दिलाकर लौटे। अक्सर जब टीम इंडिया लक्ष्य का पीछा करती थी तो धोनी अंतिम ओवर तक खेल को ले जाते थे। उनका मानना था कि गेंदबाज से ज्यादा दबाव बल्लेबाज पर होता है, लेकिन वे खुद इतने शांत रहते थे कि विपक्षी कप्तान के पसीने छूट जाते थे।

क्या बदल गया है क्रिकेट खेलने का अंदाज

आज के दौर में वनडे क्रिकेट खेलने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। आजकल के बल्लेबाज स्ट्राइक रेट बढ़ाने के चक्कर में बड़े शॉट्स खेलते हैं और जल्दी विकेट गंवा देते हैं। आधुनिक क्रिकेट में धोनी जैसा धैर्य और क्रीज पर टिके रहने की स्थिरता कम ही खिलाड़ियों में नजर आती है। धोनी अक्सर नंबर 6 या 7 पर बल्लेबाजी करते थे, जहां नॉट आउट रहने की संभावना तो होती है लेकिन मैच जिताने की जिम्मेदारी सबसे कठिन होती है। आज के फिनिशर्स अंत तक टिकने के बजाय कैमियो (छोटी और तेज पारी) खेलने पर ज्यादा ध्यान देते हैं।

आईपीएल 2026 के लापता सितारे, करोड़ों रुपये लेकर भी धोनी सहित ये दिग्गज अब तक नहीं खेले एक भी मैच!

(जीएनएस)।

आईपीएल 2026 का रोमांच अपने चरम पर है, लेकिन कई क्रिकेट फैंस के लिए यह सीजन थोड़ा फीका साबित हो रहा है। टूनार्मेंट के कुछ सबसे बड़े सितारों का मैदान से दूर रहना फैंस को पसंद नहीं आ रहा है। एमएस धोनी से लेकर मथीशा पथिराना तक कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो या तो इंजरी के शिकार हैं या टीम कॉम्बिनेशन की वजह से अब तक एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं।

धोनी अब तक नहीं खेल पाए हैं एक भी मैच (क्ढछ 2026 छंॊ२३ ठी६२)

क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि ये मैच विनर अपनी टीमों की किस्मत बदलेंगे, लेकिन फिलहाल ये केवल डगआउट की शोभा बढ़ा रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बड़े पोस्टर बॉय एमएस धोनी इस सीजन में अब तक एक भी मैच नहीं खेल सके हैं। 44 वर्षीय धोनी अपनी पिंडली की चोट से जूझ रहे हैं। हालांकि वह टीम के साथ अधिकतर मैच में सफर कर रहे हैं और मेंटॉर की भूमिका में नजर आते हैं, लेकिन उनके हाथों में दस्ताने और बल्ला न देखकर फैंस काफी मायूस हैं।

मथीशा पथिराना का इंतजार कर रहे हैं फैंस, श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना, जिन्हें डेथ ओवर का सबसे घातक हथियार माना जाता है, हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण इस सीजन में अब तक एक्शन से बाहर हैं। पिछले सीजन में डेथ ओवर्स में कहर बरपाने वाला यह गेंदबाज इस बार केकेआर की प्लेइंग-कका हिस्सा नहीं बन सके हैं। पथिराना की गैरमौजूदगी में केकेआर की डेथ बॉलिंग काफी कमजोर नजर आ रही है, जिसका फायदा विपक्षी टीमें उठा रही हैं।

पृथ्वी को मिली किस गलती की सजा? दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के लिए आईपीएल 2026 अब तक किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। कभी टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ माने जाने वाले शॉ इस पूरे सीजन में एक-एक मौके के लिए तरस गए हैं। मैनेजमेंट ने उन्हें एक भी मैच की प्लेइंग-क में जगह नहीं दी है। उनकी जगह टीम ने युवाओं और अन्य विदेशी विकल्पों पर भरोसा जताया है।

रचिन रविंद्र को नहीं मिला मौका, न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र ने पिछले आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी से लोहा मनवाया था। लेकिन इस बार वह बेंच गरम कर रहे हैं। केकेआर के पास विदेशी खिलाड़ियों की भरमार और टॉप ऑर्डर में फिन एलन के साथ कैमरुन ग्रीन की स्थिरता के कारण रचिन को मौका नहीं मिल पा रहा है। कई विदेशी खिलाड़ी के बाहर होने के बाद भी टीम में उनकी जगह नहीं बन सकी है।

सिर्फ चेन्नई और केकेआर ही नहीं अन्य टीमों में भी कई बड़े नाम मौके का इंतजार कर रहे हैं। इनमें दक्षिण अफ्रीका के कुछ तेज गेंदबाज और भारत के घरेलू क्रिकेट के चमकते सितारे शामिल हैं, जो इम्पैक्ट प्लेयर नियम के बावजूद प्लेइंग-क में जगह नहीं बना पाए हैं।

विचारधारा, राजनीति और इतिहास के सवालों को बेबाकी से उठाती है 'आखिरी सवाल'

मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र विक्की (नमाशी चक्रवर्ती) अपने प्रोफेसर गोपाल नाडकर्णी (संजय दत्त) से पीएचडी थीसिस को लेकर तीखी बहस करता है। प्रोफेसर ने उसकी आरएसएस पर आधारित रिसर्च को अस्वीकार कर दिया है। प्रोफेसर नाडकर्णी आरएसएस की विचारधारा - व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण - को विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्की उन्हें संगठन का समर्थक बताते हुए सवाल खड़े करता है। बहस धीरे-धीरे इतना उग्र रूप ले लेती है कि प्रोफेसर गुस्से में विक्की को थप्पड़ मार देते हैं। इस घटना को प्रोफेसर पल्लवी मेनन (समीरा रेड्डी) अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर देती हैं। देखते ही देखते यह मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाता है। इसके बाद विक्की प्रोफेसर के सामने 5 बड़े सवाल रखता है और कहता है कि यदि उन्हें संतोषजनक जवाब मिल गया तो वह अपनी थीसिस वापस ले लेगा। विक्की की मित्र सारा (त्रिधा चौधरी) उसे आगाह करती है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस पूरे विवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं।

कॉलेज ऑडिटोरियम में विक्की पहला सवाल उठाता है कि आखिर आरएसएस पर सरकार ने तीन बार प्रतिबंध क्यों लगाया था? इसके बाद सवाल-जवाब और विचारधाराओं की बहस का सिलसिला शुरू होता है, जो धीरे-धीरे राष्ट्रीय न्यूज चैनलों की सुर्खियाँ बन जाता है। न्यूज एंकर आदित्य (अमित साध) इस मुद्दे को प्राइम टाइम डिबेट में बदल देता है, जबकि चैनल की शो डायरेक्टर काव्या रावत (नीतू चंद्रा) भी इस पूरे विवाद में गहरी रुचि दिखाती हैं। दूसरी ओर प्रोफेसर नाडकर्णी की पत्नी प्रभा (मृणाल कुलकर्णी) उन्हें मानसिक रूप से इस चुनौतीपूर्ण बहस के लिए तैयार करती हैं। फिल्म एक साधारण अकादमिक विवाद को राष्ट्रीय स्तर की वैचारिक बहस में तब्दील कर देती है। कहानी में आरएसएस समर्थक सोच, विरोधी विचारधारा और मीडिया के प्रभाव को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

आखिरी सवाल में कैसी रही कलाकारों की परफॉर्मेंस? प्रोफेसर गोपाल नाडकर्णी के रोल में संजय दत्त बेहद संयमित और प्रभावशाली नजर आते हैं। उन्होंने अपने अभिनय में गंभीरता और भावनात्मक गहराई का बेहतरीन मेल दिखाया है। उनके संवाद और व्यक्तित्व फिल्म को मजबूत आधार देते हैं। विक्की के किरदार में नमाशी चक्रवर्ती ने गुस्से, बेचैनी और सवालों से भरे युवा की मानसिकता को प्रभावी ढंग से पर्दे पर उतारा है। यह उनके करियर की सबसे सशक्त प्रस्तुतियों में से एक मानी जा सकती है। अमित साध एक आक्रामक और स्मार्ट न्यूज एंकर के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। वहीं नीतू चंद्रा चैनल की संपादक के किरदार में सधी हुई दिखाई देती हैं। समीरा रेड्डी अपने नेगेटिव शेड्स वाले किरदार से दर्शकों को प्रभावित करती हैं। त्रिधा चौधरी और मृणाल कुलकर्णी भी अपने किरदारों के जरिए कहानी को भावनात्मक मजबूती प्रदान करती हैं।

निर्देशक अभिजीत मोहन वारंग ने इतने संवेदनशील और विवादास्पद विषय को संतुलित तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उन्होंने तथ्यों और सिनेमाई नाटकीयता के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखा है। फिल्म का पहला भाग छात्र और प्रोफेसर के बीच विचारों की टकराहट को दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ाता है। संवाद असरदार हैं और कई दृश्य लंबे समय तक दर्शकों के जहन में बने रहते हैं।

योगी ने गोरखपुर में गोड़धोइया नाला परियोजना का लिया जायजा, 15 जून तक काम पूरा करने का दिया लक्ष्य

(जीएनएस)।

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में गोड़धोइया नाला पुनरोद्धार परियोजना केवल जल निकासी व्यवस्था नहीं, बल्कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक बनाने का एक मॉडल है। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में जिन मोहल्लों में एक घंटे की बारिश से जलभराव हो जाता था, वहां अब समुचित ड्रेनेज व्यवस्था विकसित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 15 जून तक परियोजना का कार्य पूरा कर गोरखपुरवासियों को समर्पित कर दिया जाएगा, जिससे शहर के उत्तरी हिस्से की ढाई से पांच लाख आबादी सीधे लाभान्वित होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम गोड़धोइया नाला परियोजना के कार्यों का दो स्थानों (जीरो पाइंट जंगल छत्रधारी और बिछिया एसटीपी) पर स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अब तक हुए कार्यों पर संतोष जताते हुए शेष बचे कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के बाद बिछिया एसटीपी के पास उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जून में इस परियोजना के पूरा होने के साथ ही एक भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा।

प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 495 करोड़ रुपये की लागत वाले गोड़धोइया नाला परियोजना (पक्का नाला निर्माण, डायवर्जन, इंटरसेप्शन और ट्रीटमेंट की परियोजना) के कार्यों का जायजा लेने सबसे पहले इसके जीरो पाइंट जंगल छत्रधारी पहुंचे। यहां उन्होंने निर्माण कार्य, पक्के नाले में जल प्रवाह को देखने के साथ ही परियोजना के ड्राइंग मैप व माडल का अवलोकन किया।

इसके बाद मुख्यमंत्री इस परियोजना के तहत बिछिया में बन रहे एसटीपी पर पहुंचे। एसटीपी का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने यहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत 15 जून तक गोड़धोइया नाला प्रोजेक्ट के सभी काम पूर्ण हो जाएंगे। इससे इस वर्ष मानसून से पहले आधे शहर की जलभराव की समस्या दूर हो जाएगी।

परियोजना का काम पूरा होते शहर

के उत्तरी छोर की करीब पांच लाख आबादी को बड़ी राहत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में जल भराव एक बड़ी चुनौती थी। इससे जल जनित और मच्छर जनित बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा था। अब इस समस्या का समाधान हो गया है।

उन्होंने कहा कि गोड़धोइया नाला अब न केवल अतिक्रमण मुक्त हो गया है बल्कि जल भराव की समस्या को दूर करने का भी बड़ा माध्यम बन रहा है। उन्होंने बताया कि वन महोत्सव के दौरान इस नाले के दोनों तरफ पौधरोपण अभियान को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा अब गोड़धोइया नाले में कोई सीवर और कोई गंदा नाला नहीं गिर रहा है, इसमें केवल शुद्ध पानी प्रवाहित होगा। सीवर और ड्रेनेज के लिए इसमें दोनो तरफ अलग से लाइन बिछायी गयी है, जो भूमिगत है। उन्होंने कहा कि करीब 9.5 किमी का आरसीसी से निर्मित किया नाला 9 मीटर चौड़ा है।

वर्षा काल में यह नाला गोरखपुर महानगर के जल को रामगढ़ताल, तरकुलानी होते हुए राप्ती नदी में छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि इस नाले में 14 कलवर्ट/ब्रिज बनाए गए हैं जो इस पार से उस पार तक आवागमन को आसान बनाएंगे। इस नाले के दोनों तरफ सड़क के निर्माण कार्य को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे इस क्षेत्र के लोगों को एक वैकल्पिक मार्ग प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में 38 एमएलडी की एसटीपी और 61 एमएलडी क्षमता के पंपिंग स्टेशन का भी निर्माण किया गया है। इसके बन जाने से महानगर के बड़े इलाके को जल जमाव, मच्छर व बीमारी की समस्या का स्थायी समाधान प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि मोहल्लों की गंदगी अब सीवर लाइन से सीधे एसटीपी तक पहुंचाकर उसका शोधन होगा। इससे इस क्षेत्र की लगभग 5 लाख आबादी लाभान्वित होगी।

ईज आफ लिविंग का माडल बन रहा गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदितयनाथ ने कहा कि किसी भी शहर की सूरत को बदलने, लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और ईज ऑफ लिविंग को सर्वोत्तम बनाने के लिए क्या मॉडल होना चाहिए, आज गोरखपुर शहर उसका एक उदाहरण बन रहा है। पिछले 9 वर्ष में गोरखपुर महानगर ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं।

आज गोरखपुर में चारों दिशाओं से फोरलेन सड़कों की कनेक्टिविटी है। गोरखपुर में रामगढ़ताल का सुंदरीकरण हो चुका है। गोरखपुर में जल निकासी की उचित व्यवस्था, खुले नालों को बंद करने की व्यवस्था तथा उसमें बहने वाले जल को उपचारित करने की व्यवस्था की जा रही है।

उन्होंने कहा कि कभी छोटी नदी रही गोड़धोइया नाला एक गंदा नाला बन चुका था। यह जंगल छत्रधारी होते हुए रामगढ़ताल में गिरता था। पहले यह नाला गंदगी, प्रदूषण, मच्छर, जलभराव का कारण बन जाता था। आज इसका पुनरुद्धार कर इसे अत्याधुनिक माडल के रूप में खड़ा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने की स्वच्छता में जनता से सहयोग की अपील

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज गोरखपुर विकास का मॉडल बना है। नगर निगम गोरखपुर स्वच्छता का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है और गोरखपुर विकास प्राधिकरण कन्वेंशन सेंटर तथा नए-नए आवासीय कॉलोनी का निर्माण कर रहा है। आज गोरखपुर के विकास के लिए अलग- अलग योजनाओं के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

यह गोड़धोइया नाला भी उसी का एक हिस्सा है। 15 जून तक इसके निर्माण कार्य पूर्ण होने पर इसका उद्घाटन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आज जब नगर निगम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत के मिशन को आगे बढ़ाने में प्रतिबद्ध है तो हम नागरिकों का भी यह दायित्व है कि हम प्लास्टिक का उपयोग न करे, नालों में प्लास्टिक, कपड़े, गंदगी आदि न फेंके।

यदि ऐसा हम करेंगे तो हमारा शहर स्वच्छ व सुंदर होगा। इससे वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ी विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित होगी और गोरखपुर समृद्धि के नए लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ल, महापौर मंगलेश श्रीवास्तव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, भाजपा के महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, क्षेत्रीय पार्षद आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

रामगढ़ताल में जाएगा शोधित पानी

शहर के बिछिया जंगल तुलसीराम पश्चिमी, शिवपुर शहबाजगंज, जंगल शालिग्राम, बिछिया जंगल तुलसीराम पूर्वी, रेलवे बिछिया कॉलोनी, शाहपुर, भेड़ियागढ़, घोसीपुरवा, सेमरा, बशारतपुर, मानबेला, रासीनगर, लोहिया नगर, जंगल नकहा, राम जानकी नगर, शक्तिनगर एवं चक्सा हुसैन से जनित सीवेज जो नाले में बहते हैं, उन्हें 38 एमएलडी एसटीपी पर शोधित कर रामगढ़ताल में प्रवाहित किया जाएगा।

नाला अतिक्रमण मुक्त होने से इसके कैचमेंट एरिया (अधिग्रहण क्षेत्र) में आने वाली विभिन्न कॉलोनियों में जलभराव की समस्या का भी निदान हो जाएगा।

48 घंटे के अंदर सहायता पहुंचाने प्रभावित परिवारों के द्वार पहुंचे मंत्री-अफसर, मृतकों के परिवार को दिए 4-4 लाख के चेक

(जीएनएस)।

लखनऊ। प्रदेश में बीते बुधवार को आई आंधी-बारिश और वज्रपात से कई जिलों में भारी तबाही और 113 लोगों की मौतों के बाद 48 घंटे के अंदर पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश का असर दिखाई देने लगा है। प्रभावित जिलों में मृतकों के परिवार को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

पीड़ित परिवारों की मदद और हालचाल के लिए अधिकारियों के साथ ही जिलों के प्रभारी मंत्री भी पहुंचे। योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। किसानों, पशुपालकों को भी जल्द सहायता पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। प्रयागराज में आंधी से 27 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 14 शवों का पोस्टमार्टम कराया गया, जबकि 13 का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम के किया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतकों के स्वजन के खातों में शुक्रवार सुबह तक सहायता राशि भेज दी गई। बाकी मामलों में एसडीएम रिपोर्ट के आधार पर शाम तक भुगतान कराया गया। प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह स्वयं पीड़ित परिवारों के घर पहुंचे और सांत्वना दी। अस्पताल में भर्ती पांच घायलों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। संभल में प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मृतकों के स्वजनों को चार-चार लाख रुपये मिलने के प्रमाण पत्र सौंपे।

उन्नाव में छह मृतकों के आश्रितों को कुल 24 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। फतेहपुर में 11 मृतकों में से नौ परिवारों को 36 लाख रुपये की सहायता राशि मिल गई है, जबकि दो मामलों में प्रक्रिया जारी है। कानपुर देहात में दो मृतकों के परिवारों के खातों में आठ लाख रुपये भेजे गए हैं। बरेली मंडल में आंधी से 11 लोगों की मौत हुई थी।

पीड़ितों से मिलकर आर्थिक सहायता चेक सौंपे

इनमें बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर के पांच पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे दिया गया है, जबकि बाकी परिवारों को शनिवार तक राहत राशि देने की तैयारी है। लखीमपुर खीरी में प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल, हरदोई में मंत्री असीम अरुण ने हरदोई, अंबेडकर नगर में मंत्री गिरीश चंद्र यादव, बदायूं में मंत्री गुलाब देवी, बरेली में मंत्री जेपीएस राठौर ने पीड़ितों से मिलकर उन्हें आर्थिक सहायतों के चेक सौंपे।

कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं, अब मंदिरों का हो रहा सुंदरीकरण', महाराजगंज में माफियाराज पर बरसे सीएम योगी

(जीएनएस)।

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब आपका वोट सही जगह पड़ता है, तब विकास, सुरक्षा, रोजगार और सुशासन सुनिश्चित होता है, लेकिन एक गलत वोट जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, माफियावाद, अराजकता और गरीबों की जमीनों पर कब्जे जैसी दुष्प्रवृत्तियों को जन्म देता है। डबल इंजन सरकार ने इन प्रवृत्तियों पर प्रभावी रोक लगाकर प्रदेश में सुशासन और विकास का नया वातावरण तैयार किया है।

महराजगंज समेत पूरे पूर्वांचल को माफिया, दंगा व भय के माहौल से बाहर निकालकर विकास, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, मजबूत सड़क नेटवर्क, सिंचाई, रोजगार और सुरक्षा से जोड़ा है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को महराजगंज में ₹208 करोड़ से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करने के उपरांत उपस्थित जन-समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र एवं टूलकिट भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा व सहयोगी दलों के विधायक बनने के बाद विधानसभा क्षेत्रों में मंदिरों के सौंदर्यीकरण और जनसुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई। पहले जनता के करोड़ों रुपये कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल पर खर्च होते थे, जबकि अब वही धन मंदिरों में बेहतर सुविधाएं विकसित करने और आम जनता के हित में लगाया जा रहा है। महराजगंज में दिख रहा विकास सही सांसद और विधायक चुनने का परिणाम है। बनेलिया माई के नाम पर रोहिन नदी पर बैराज का निर्माण हो या गोरखपुर से सोनौली तक फोरलेन मार्ग का कायाकल्प, ये सब जनता के एक सही वोट की ताकत से संभव हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले महराजगंज इंसेफेलाइटिस, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, अराजकता,

माफियावाद और पलायन की त्रासदी झेल रहा था। दिमागी बुखार मासूम बच्चों की जान ले रहा था, सड़कें गड्ढों में तब्दील थीं, बिजली व्यवस्था चरमराई हुई थी, गरीबों की जमीनों पर कब्जे आम थे और किसान, नौजवान व बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार बनने के बाद महराजगंज की तस्वीर बदल गई। इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण हुआ, मेडिकल कॉलेज संचालित हुआ, नौतनवा, फरेंदा, चौक, सिसवा, श्यामदेउरवा, घुघली और पनियरा बेहतर सड़क नेटवर्क से जुड़ गए तथा गोरखपुर-सोनौली फोरलेन बनने से यात्रा समय दो घंटे से घटकर 45-50 मिनट रह जाएगा। गोरखपुर के नए बाईपास, ठूठीबारी से जिला मुख्यालय तक मजबूत सड़क नेटवर्क, पुलों के निर्माण और रोहिन नदी पर बने बनेलिया माई बैराज से क्षेत्र में कनेक्टिविटी और सिंचाई दोनों को नई ताकत मिली है। वनटांगिया गांवों को पट्टा, मतदाता पहचान और सरकारी योजनाओं से जोड़कर सम्मानजनक जीवन देने का काम भी डबल इंजन सरकार ने किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने गरीबों की पीड़ा को कभी नहीं समझा, जबकि डबल इंजन सरकार हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उनके जीवन में बदलाव ला रही है। वनटांगिया गांवों में भी राजस्व गांवों जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर गरीब को आवास, हर घर को शौचालय, राशन और आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है, जबकि गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। महराजगंज के सैकड़ों नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए हैं और किसान सिंचाई, बीज, ट्रैक्टर, उन्नत खेती तथा सरकारी क्रय केंद्रों का लाभ उठा रहे हैं। माफिया का आतंक समाप्त हो चुका है, गरीबों की जमीनों पर कब्जा नहीं हो सकता, बेटियां सुरक्षित हैं और किसी में भी गोहत्या या जबरन अत्याचार करने का दुस्साहस नहीं बचा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सदियों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राममंदिर निर्माण हुआ है। महराजगंज के हजारों नौजवान, महिलाएं, किसान, व्यापारी और बुजुर्ग भी राममंदिर आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। 492 वर्ष बाद मंदिर का शिलान्यास हुआ और 496 वर्ष बाद प्रधानमंत्री के कर-कमलों से अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। दुनिया का सबसे भव्य राममंदिर अयोध्या में बना है और अखंड रामायण पाठ के बीच ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान राम और हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हों। डबल इंजन सरकार में भव्य राममंदिर और काशी विश्वनाथ धाम जैसे ऐतिहासिक कार्य संभव हुए, जबकि सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां इन कार्यों में हमेशा बाधा बनती रहीं। इसी बाधा को पश्चिम बंगाल की जनता ने भी हमेशा के लिए उखाड़ फेंका है। इसलिए आप सबसे यही आग्रह करने आया हूं कि इन जनप्रतिनिधियों के साथ मजबूती से खड़े रहिए।

भारत-नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत और सीमावर्ती क्षेत्र की संवेदनशीलता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नौतनवा, फरेंदा और सोनौली जैसे क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि यहां का नागरिक कभी खुद को पिछड़ा महसूस न करे। भारत और नेपाल सिर्फ दो पड़ोसी देश नहीं, बल्कि साझा संस्कृति, आस्था और रोटी-बेटी के अटूट रिश्ते से जुड़े मित्र राष्ट्र हैं। बौद्ध परिपथ और अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े महराजगंज, नौतनवा और फरेंदा का विकास केवल सुविधा नहीं, बल्कि सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से भी बेहद जरूरी है।

आंधी ने छीनी जिंदगी.. योगी सरकार बनी सहारा, पीड़ित परिवारों तक पहुंचे मंत्री, सौंपे 4-4 लाख के चेक

(जीएनएस)।उत्तर प्रदेश में बीते दिनों आई तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई. कई जिलों में मकान ढह गए, पेड़ और बिजली के पोल गिर पड़े, जबकि कई लोगों की जान चली गई. अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. कहीं शादी वाले घर में मातम छा गया तो कहीं बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया. हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित इलाकों में पहुंचने और पीड़ित परिवारों को राहत देने के निर्देश दिए. इसके बाद अलग-अलग जिलों में मंत्री खुद गांवों तक पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मिले और उन्हें आर्थिक सहायता के चेक सौंपे.

उन्नाव में छह लोगों की मौत, मंत्री धर्मपाल सिंह ने बांटे चेक

उन्नाव में तेज आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की वजह से छह लोगों की मौत हो गई. इसके बाद जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह विकास भवन पहुंचे और मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक सौंपे. मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला कोई नहीं कर सकता. जान की भरपाई कभी नहीं हो सकती, लेकिन सरकार पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने का काम कर रही है. उन्होंने परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है.

मीरजापुर में आकाशीय बिजली और तूफान की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों के घर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंचीं. उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया. चुनार और सदर तहसील के गांवों में पहुंचकर उन्होंने दोनों पीड़ित परिवारों को चार-चार लाख रुपये की राहत सहायता दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि दुख की इस

घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है.

भदोही में तूफान ने एक शादी वाले घर को मातम में बदल दिया. जानकारी के मुताबिक, शादी के बाद कुछ लोग गांव के मंदिर में मोरी चढ़ाने गए थे. तभी तेज आंधी में मंदिर के पास खड़ा पुराना नीम का पेड़ गिर पड़ा. हादसे में कई लोग उसकी चपेट में आ गए. प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा प्रभावित गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने 13 प्रभावित परिवारों को चार-चार लाख रुपये के डेमो चेक सौंपे. मंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जनता के सुख-दुख में बराबर की भागीदार है. प्रशासन के मुताबिक, जिले में अब तक 16 लोगों की मौत, 12 लोगों के घायल होने, 20 मकानों के क्षतिग्रस्त होने और 28 पशुओं की मौत की घटनाएं दर्ज की गई हैं.

रायबरेली में प्रभावित परिवारों को राहत और आवास योजना का लाभ

रायबरेली में भी बेमौसम बारिश और आंधी से कई परिवार प्रभावित हुए. उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने खीरों ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में पीड़ित परिवारों को राहत राशि वितरित की. यहां जनहानि, पशुहानि, मकान क्षति और घायलों को आर्थिक सहायता दी गई. साथ ही दो लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रमाण पत्र भी सौंपे गए. मंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि राहत वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और पात्र लोगों तक समय से मदद पहुंचे.

लखीमपुर खीरी के जमुनिया कढ़ीले गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान एक मकान की छत गिर गई. हादसे में 40 वर्षीय रतिराम की मौत हो गई. घटना के बाद जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने मृतक की पत्नी और बच्चों को चार लाख रुपये की दैवीय आपदा सहायता, गृह अनुदान और राशन किट सौंपी. मंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और महिला सशक्तिकरण में भी मदद करेगी. जिलाधिकारी ने बताया कि परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना, पारिवारिक लाभ योजना, निराश्रित महिला पेंशन और सीएम बाल सेवा योजना से भी जोड़ा जा रहा है.

प्रयागराज में प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हंडिया, फूलपुर और सोरांव तहसील के प्रभावित गांवों का दौरा किया. उन्होंने मृतकों के परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की देरी न हो. मंत्री ने कहा कि जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं या फसलें खराब हुई हैं, उनका तुरंत सर्वे कराया जाए और नियमानुसार सहायता दी जाए. साथ ही बिजली, पेयजल और यातायात व्यवस्था जल्द बहाल करने के निर्देश भी दिए गए.

हरदोई में मंत्री असीम अरुण ने आकाशीय बिजली की चपेट में आई मृतक युवती के परिवार से मुलाकात की और बताया कि चार लाख रुपये की सहायता राशि खाते में भेज दी गई है.

संभल में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई. बदायूं में मंत्री गुलाब देवी ने तूफान से प्रभावित परिवारों को चेक सौंपे, जबकि बरेली में मंत्री जेपीएस राठौर ने मृतकों के परिजनों के साथ-साथ मकान और पशुहानि झेलने वाले लोगों को भी सहायता राशि वितरित की.

प्रदेश सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाई जाए और किसी भी पीड़ित परिवार को मदद के लिए भटकना न पड़े.

अधूरी सड़क का निर्माण, ठेकेदार के दावों पर बवाल, जांच के लिए पहुंची लखनऊ की टीम

(जीएनएस)।

कुशीनगर, रामकोला-कसया मुख्य मार्ग की जर्जर स्थिति और अधूरे निर्माण को लेकर शुक्रवार को लखनऊ से आई लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की जांच टीम ने टेकुआटार बाजार में स्थलीय निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने अधिकारियों को घेरकर सड़क की बदहाली और निर्माण में अनियमितताओं को लेकर जमकर विरोध जताया। कहा कि ठेकेदार बिना काम कराए भुगतान कराने की कोशिश में हैं। इकेदार का दावा है कि 2022 में सड़क का निर्माण कराया था। जबकि सड़क वैसे ही टूटी पड़ी है।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय टीम में मुख्य अभियंता सीपी गुप्ता, अधीक्षण अभियंता वेद नारायण और अधिशासी अभियंता राजेश कुमार शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान स्थानीय पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी मौजूद रहे। टीम ने सड़क का पैदल निरीक्षण कर उसकी स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों को सड़क पर घुमाकर गड्ढों और टूटे हिस्सों की स्थिति दिखाई।

ग्रामीणों का कहना था कि वर्ष 2015 से यह मार्ग लगातार बदहाल है और अब तक इसका पूर्ण रूप से पुनर्निर्माण नहीं कराया गया। सड़क की खराब हालत के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में टेकुआटार क्षेत्र में दो लोगों की सड़क हादसे में मौत भी हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने 7 मई 2026 को हुए धरना-प्रदर्शन का भी हवाला देते हुए कहा कि केवल गड्ढों में गिट्टी डालकर खानापूर्ति की गई, लेकिन सड़क का वास्तविक निर्माण नहीं कराया गया।

इस दौरान ग्रामीणों ने जांच टीम का घेराव भी किया और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। निरीक्षण के दौरान ठेकेदार ने दावा किया कि सड़क का निर्माण वर्ष 2022 में कराया गया था, लेकिन ग्रामीणों ने इसे गलत बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना था कि वर्ष 2015 के बाद से इस मार्ग पर कोई पूर्ण निर्माण कार्य नहीं हुआ है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम ने पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया।

अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कसया-रामकोला मार्ग पर अनुबंधित 11 किलोमीटर में से केवल 2.5 किलोमीटर कार्य और देवरिया-कसया मार्ग पर 6 किलोमीटर में से मात्र 2 किलोमीटर कार्य ही कराए जाने की बात सामने आई है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे और सड़क निर्माण में पारदर्शिता की मांग करते रहे।

दोनों सड़कों के लिए 3.90 करोड़ का अनुबंध हुआ था। इसमें निर्माण कार्य के सापेक्ष 1.20 करोड़ का भुगतान फर्म को कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सड़क मरम्मत के लिए टेंडर हुआ था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं कराने के चलते भुगतान नहीं किया जा रहा था। इसकी शिकायत ठेकेदार शासन में की है।